भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2727

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2024 को दिया जाना है ।

16 श्रावण, 1946 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियां

2727. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी :
श्री सी. एन. अन्नादुरई :
श्री विष्णु दत्त शर्मा:
श्री नवसकनी के.:
श्री जी. सेल्वम:
श्री दयानिधि मारन:
श्री एम. के. राघवन:
डॉ. भोला सिंह:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण संकुलों की कुल संख्या और तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की सूची का ब्यौरा क्या है और प्राप्त निवेश, सृजित रोजगार, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, के संदर्भ में प्रत्येक संकुल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया पहल के एक भाग के रूप में वर्ष 2025-26 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर 24 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग स्नातकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रति शिक्षित बनाने के लिए उन्हें कौल प्रदान करने की कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) हेतु निधियां आवंटित की हैं और क्या सरकार के पास पीएलआई योजनाओं की शुरुआत के बाद से अब तक देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की स्थिति के संबंध में कोई आंकड़े और कोई लक्ष्य हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल और तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए किसी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा सहायता उपकरणों को आम आदमी के लिए वहनीय बनाया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन में केरल के योगदान की जानकारी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ज) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) और ईएमसी 2.0 योजनाओं के तहत देश भर के 19 राज्यों में 24 ईएमसी परियोजनाएं और 4 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्वीकृत किए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ("एमईआईटीवाई") की 'संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस)' के अंतर्गत तमिलनाडु से 33 आवेदन प्राप्त हुए। तमिलनाडु राज्य में विनिर्माण शुरू करने वाली कंपनियों

द्वारा किया गया कुल उत्पादन 1,38,452 करोड़ रुपये है। एम-एसआईपीएस के तहत स्वीकृत उत्पादों के लिए ऐसी कंपनियों द्वारा किया गया कुल निर्यात 57,720 करोड़ रुपये है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (स्पेक्स)' के तहत तमिलनाडु में 7 आवेदनों को मंजूरी दी गई। तमिलनाडु में इन आवेदकों द्वारा कुल निवेश 6,852 करोड़ रुपये से अधिक है।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत तमिलनाडु स्थित 4 आवेदकों को मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। अकेले एप्पल फोन के निर्माण में तमिलनाडु में 43 हजार से अधिक कर्मचारी लगे हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना के अंतर्गत, मेसर्स केरल औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम (केआईएनएफआरए) ने केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले के कनयन्नुरतालुक के कक्कनाड गांव में 66.87 एकड़ क्षेत्र में ग्रीनफील्ड ईएमसी की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। ईएमसी में अपनी सुविधाएं स्थापित करने के लिए 12 कंपनियों ने विनिर्माण स्थान लिया है।

सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और कोम्पोनेंट्स ईकोसिस्टम के विकास पर केंद्रित निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है:

(i) इलेक्ट्रॉनिक कोम्पोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स (स्पेक्स) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना 01.04.2020 को अधिसूचित की गई थी और 31.03.2024 तक आवेदन स्वीकार किए जाने के लिए खुली थी। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक कोम्पोनेंट्स, ई-कचरा रीसाइक्लिंग, मैकेनिक्स, माइक्रो/नैनो-इलेक्ट्रॉनिक कोम्पोनेंट्स, सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) पॉलीसिलिकॉन, एसपीवी वेफर्स और सौर सेल, विशेष उप-असेंबली और उपरोक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। 30.06.2024 तक, स्पेक्स योजना के तहत 9066.96 करोड़ रुपये का वृद्धिशील निवेश किया गया था। इससे 30 जून, 2024 तक 19,902 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है।

(ii) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) योजना**:** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक कोम्पोनेंट्स और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित मोबाइल फोन मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) योजना 01.04.2020 को अधिसूचित की गई थी। यह योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए उन कंपनियों को भारत में निर्मित और लक्षित सेगमेंट्स जैसे मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कोम्पोनेंट्स के अंतर्गत वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष की तुलना में) पर 3% से 6% का प्रोत्साहन देती है । 30 जून, 2024 तक पीएलआई योजना के तहत 8,390 करोड़ रुपये का वृद्धिशील निवेश किया गया था। इससे 30 जून, 2024 तक 5,14,960 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है।

एमईआईटीवाई ने 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी जनशक्ति के री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है। इनमें एआई, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, बिग डेटा और एनालिटिक्स, आईओटी, वर्चुअल रियलिटी, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, 3डी प्रिंटिंग और वेब 3.0 शामिल हैं।

सरकार ने 'विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना' शुरू की है जिसका उद्देश्य एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) और आईटी/आईटी सक्षम सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) क्षेत्रों में पीएचडी की संख्या बढ़ाना है।

113 शैक्षणिक संस्थानों/आरएंडडी संगठनों/स्टार्ट-अप्स/एमएसएमई में कार्यान्वित किए जा रहे चिप्स टू स्टार्टअप (सी2एस) कार्यक्रम के तहत, 85,000 उच्च गुणवत्ता वाले और योग्य इंजीनियरों को कई क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इनमें 5 साल की अवधि में बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण (वीएलएसआई) और एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन के साथ-साथ 175 एएसआईसी (एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट), 20 सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी) के कार्यशील प्रोटोटाइप, 30 एफपीजीए आधारित डिज़ाइन और 30 आईपी कोर का विकास शामिल है।

****